

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष – 01

अंक – 335

बेमेतरा, मंगलवार 22 जुलाई 2025

रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित

कुल पेज – 8

मूल्य – 5 रुपये

पहला कॉलम

हिमाचल में कल से तीन दिनों तक होगी भारी बारिश, बाढ़ की भी चेतावनी

शिमला। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 22 23 व 24 जुलाई को भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई है। 22 जुलाई को चंबा, किन्नौर और लाहुल स्पीति को छोड़कर प्रदेश के अन्य जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 22 जुलाई को कांगडा, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आने की भी चेतावनी दी गई है। इसके अलावा, 22 जुलाई को मंडी और ऊना में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। हालांकि, अधिकांश स्थानों पर मौसम साफ रहने का अनुमान है। शनिवार को शिमला सहित प्रदेश के कई इलाकों में खिली धूप के साथ दिन की शुरुआत हुई, लेकिन शाम के समय बादल छाने के साथ धुंध भी छा गई।

यूपी पुलिस ने एक और धर्मांतरण रैकेट का किया पर्दाफाश, 10 लोग गिरफ्तार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक और बड़े धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह प्रदेश में युवतियों को बरगलाकर, प्रलोभन देकर और कट्टरपंथी सोच के जरिए धर्मांतरण कराने में संलिप्त था। पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए विभिन्न राज्यों से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने बताया कि सीएम योगी के निर्देश पर अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए प्रदेशभर में मिशन अस्मिता प्रदेशभर में मिशन अस्मिता चलाया जा रहा है। ऐसे में पुलिस को आगरा से दो सगी बहनों के लापता होने की सूचना मिली। पुलिस ने मामले की जांच की तो अवैध धर्मांतरण का पूरा खेल सामने आया। जांच में पता चला कि दोनों लड़कियों का ब्रेनवॉश कर धर्मांतरण किया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले की तह तक जाना शुरू किया। इस दौरान कई चौकाने वाले तथ्य सामने आए। डीजीपी ने बताया कि अवैध धर्मांतरण के लिए कनाडा, अमेरिका और दुबई समेत कई देशों से करोड़ों रुपए की अंतरराष्ट्रीय फंडिंग मिली थी।

चाय की दुकान पर तृणमूल नेता की बम मारकर हत्या

बीरभूम। सत्तारूढ़ तृणमूल के राज में लगातार तृणमूल के कर्मी, समर्थक और नेताओं की हत्या की घटनाओं से बंगल की पुलिस व्यवस्था खुद सवालों के घेरे में आ गई है। बीरभूम ज़िले में बम से हमले में तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता बाइतुल्ला शेख (40) की मौत हो गई। आंकड़ों की बात करे तो पिछले नौ दिनों में तृणमूल कांग्रेस नेताओं पर हुआ यह चौथा जानलेवा हमला है। उक्त ठीक तब घटी जब तृणमूल के द्वारा 21 जुलाई के दिन होने वाले पार्टी की शहीद दिवस रैली की तैयारी की जा रही थी। लेकिन शनिवार रात को बीरभूम जिले के मल्लारपुर थाना अंतर्गत विधियाग्राम गांव में तृणमूल नेता बाइतुल्ला शेख की बम मारकर हत्या कर दी गई।

मोदी ने की विपक्षी नेताओं की तारीफ

दल हित में मत भले न मिले, पर देश हित में मन जरूर मिले.....

नई दिल्ली/ एजेंसी

संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के बाहर मीडिया से बात की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की स्थिति से रू-बरू कराने के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों का दौरा करने वाले बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों की सराहना की। इन प्रतिनिधिमंडलों ने आतंकवादियों के आका पाकिस्तान को बेनकाब करने में अहम योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'देश ने एकता की ताकत देखी है। इसलिए सदन के सभी सांसदगण इसे ताकत दें, इसे आगे बढ़ाएं और मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि हर राजनीतिक दल का अपना एजेंडा होता है, अपनी भूमिका होती है, लेकिन मैं इस सच्चाई को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले...' इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि मानसून सत्र एक 'विजय उत्सव' है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सैन्य शक्ति और क्षमता का प्रदर्शन हुआ। पीएम मोदी ने कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों ने अपने निर्धारित



लक्ष्यों को शत-प्रतिशत हासिल किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सशस्त्र बलों ने 22 मिनट के भीतर आतंकवाद के आकाओं को उनके घरों में घुसकर मारा, उनके ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने बिहार में पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी और हमारी सेना ने हमारी सैन्य शक्ति बहुत कम समय में ही साबित कर दी। दुनिया भी 'मेड इन इंडिया' की सैन्य क्षमता की ओर आकर्षित हुई है। पीएम मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सत्र के दौरान सांसद एक स्वर में और विजयी भावना के साथ इन

भावनाओं को व्यक्त करेंगे, जिससे भारत की सैन्य क्षमता मजबूत होगी, लोगों को प्रेरणा मिलेगी और मेड इन इंडिया रक्षा क्षमताओं को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पहलगाम में हुए क़त्ल नरसंहार ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। हमले ने आतंकवाद और उसकी जड़ों की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। पीएम मोदी ने नक्सलवाद के खिलाफ अपनी सरकार की निर्णायक कार्रवाई की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि लाल गलियारे अब हरित विकास क्षेत्रों में बदल रहे हैं। देश शुरू से ही हिंसक घटनाओं से जूझ रहा है।

जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू, लोकसभा में 145, राज्यसभा में 63 सांसदों ने दिया

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। 21 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलेगा। सत्र का पहला दिन हंगामे से भरा रहा। संसद में विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया। दरअसल, दोनों सदनों में कार्यवाही की शुरुआत होते ही सदस्यों ने हंगामा किया। विपक्ष ने सत्र के पहले दिन ही अपने तैवर दिखा दिए। इसके साथ ही जाहिर कर दिया कि वह ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर सरकार को थोड़ी भी ढील देने के मूड में नहीं है। सोमवार मानसून सत्र की शुरुआत के साथ विपक्ष ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम वाले दावे को लेकर सदन में हंगामा किया। इसके अलावा हंगामा के बीच ही राज्य सभा में एक बिल को पारित किया गया। मानसून सत्र के पहले दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया सोमवार दोपहर से शुरू हो गई।



कहीं न कहीं कांवड़ यात्रा की सुरक्षा में बड़ी चूक

सरधना में गंगनहर में बहते मिले चार शव,कांवड़ यात्रा के बीच हड़कंप,पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा

मेरठ / एजेंसी

मेरठ के सरधना में कांवड़ यात्रा के बीच सोमवार को मेरठ जिले के सरधना क्षेत्र में गंगनहर में एक के बाद एक चार अज्ञात शव बहते हुए नजर आए। शवों को अटेरना पुलिस चौकी और सरधना गंगनहर पुल के पास देखा गया, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने जब शवों को गंगनहर में बहते देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन थाना प्रभारी मौके पर आकर केवल भीड़

हटाकर चले गए, शवों को बाहर निकालने का कोई प्रयास नहीं किया गया। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि पुलिस का यही रवैया पहले भी रहा है। पिछले सप्ताह भी मानपुरी गांव, सरधना पुल और अहमदाबाद के पास इसी तरह तीन शव गंगनहर में बहते हुए मिले थे, जिनका जिम्मा एक थाने से दूसरे थाने पर डालकर औपचारिकता निभा दी गई। अब लगातार शव



श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह केवल दुर्घटना या आत्महत्या नहीं, बल्कि कहीं न कहीं कांवड़ यात्रा की सुरक्षा में बड़ी चूक भी हो सकती है। लोगों की मांग है कि शवों की शिनाख्त कराकर मामले की गहन जांच की जाए। पुलिस की ओर से अब तक शव निकालने या शिनाख्त की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे न केवल कांवड़ यात्रा की सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न लगा है, बल्कि प्रशासन की कार्यशैली पर भी।

101 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

केरल के पूर्व सीएम अच्युतानंदन का निधन

केरल। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन का सोमवार को तिरुवनंतपुरम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 101 वर्ष के थे। वह 2006 से 2011 तक मुख्यमंत्री रहे। अच्युतानंदन 2019 में मामूली स्ट्रोक के बाद सार्वजनिक जीवन से दूर हो गए थे। उसके बाद से वे अपने बेटे वी. अरुण कुमार के तिरुवनंतपुरम स्थित आवास पर जीवन व्यतीत कर रहे थे। अनुभवी कम्युनिस्ट और स्वतंत्रता सेनानी केरल में कम्युनिस्ट आंदोलन के एक मजबूत प्रतीक थे



और दशकों तक राज्य की राजनीति में उनकी उपस्थिति बहुत मजबूत थी। विपक्ष के एक बुझारू नेता के रूप में, अच्युतानंदन वंचितों और कठिन सार्वजनिक मुद्दों के लिए एक ध्वजवाहक थे।

बांग्लादेश एफ-7 प्लेन क्रैश

16 छात्र समेत 19 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल हुए

ढाका/ एजेंसी

बांग्लादेशी वायुसेना का एक एफ-7 प्रशिक्षण विमान सोमवार को कॉलेज परिसर में हादसे का शिकार हो गया। विमान कॉलेज की बिल्डिंग से जा टकराया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 160 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के वक्त माइलस्टोन

कॉलेज में बच्चे मौजूद थे। प्लेन क्रैश होने के बाद स्कूल-कॉलेज में अफरातफरी मच गई। मौके पर अग्निशमन और बचाव दलों ने पड़ोचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया है। नेशनल बर्न इंस्टीट्यूट के अधिकारी प्रोफेसर मोहम्मद सईदुर रहमान ने बताया कि वायुसेना का विमान माइलस्टोन कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जिसमें विमान के पायलट सहित कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई।

हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी घटना की पुष्टि की है। सूचना मिलने पर बांग्लादेशी सेना के सदस्य, अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा की आठ गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचीं और बचाव अभियान शुरू किया। बांग्लादेश सेना के जनसंपर्क कार्यालय ने बताया कि वायुसेना का प्रशिक्षण विमान ख-7 ब्रेड्डू ढाका के उत्तरा क्षेत्र के दियाबारी इलाके में



माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज कि हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि

प्रशिक्षण विमान ने दोपहर लगभग 1:06 बजे उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के तुरंत बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद विमान में आग लग गई। आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल की बुझाने के लिए अग्निशमन दल की आठ दमकल मौके पर पहुंच गईं। माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज के प्रवक्ता ने कहा कि विमान स्कूल के गेट के पास गिरा। स्कूल परिसर में जहां विमान हादसा हुआ, वहां कक्षा चल रही थी।

घायलों को एक-एक करके बाहर निकाला जा रहा है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक एक प्रत्यक्षदर्शी सादमान रुहसिन ने बताया कि विमान स्कूल की इमारत से टकराया। सेना और अग्निशमन सेवा के सदस्य घटनास्थल पर पहुंचे और छात्रों तथा अभिभावकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। सेना के जवान परिसर में जहां विमान हादसा लाते देखे गए।

संपादकीय

आतंकवाद अब पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन गया है। इसे जड़ से खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयास के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। इसका कारण है कुछ देशों की कथनी और करनी में अंतर, जो कई अवसरों और मंचों पर साफ नजर आता है। इस मामले में भारत की नीति और नीयत पूरी तरह स्पष्ट है कि आतंक को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं, पाकिस्तान जैसे मुल्क दोहरे मापदंड अपना कर एक तरफ खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताते हैं, दूसरी ओर अपनी जमीन पर

भारत का रूस के साथ व्यापार, खासतौर से तेल आयात, अब अमेरिका और पश्चिमी देशों को बहुत अखरने लगा है। उन्‌होंने भारत पर तलवार लटका दी है। यह किसी ‘अग्निपरीक्षा’ से कम नहीं है। भारत पर अपनी ऑयल स्रट्रेंटेंजी को बदलने का भारी दबाव है। रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते भारत का रूसी तेल आयात पश्चिमी देशों के बयानबाजी का केंद्र बना हुआ है। नाटो के महासचिव मार्क रूटे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं ने भारत, चीन और ब्राजील को रूस के साथ व्यापार जारी रखने पर सेकेंडरी सैंव?शनस और भारी टैरिफ की चेतावनी दे दी है। इन धमकियों को रूस पर दबाव डालने की रणनीति का हिस्‌सा माना जा रहा है ताकि वह शांति वार्ता के लिए गंभीर हो। हालांकि, भारत ने अब तक रूस से अपने तेल आयात में कटौती नहीं की है। अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को उसने सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है।

अमेरिका-यूरोप ने लटका दी है तलवार... रूस के कारण भारत की ‘अग्निपरीक्षा’

(अमित शुक्ला)

भारत और रूस के बीच व्यापारिक रिश्ते पश्चिमी देशों को परेशान कर रहे हैं। विशेष रूप से तेल के आयात को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देश कुछ उन्‌यादा ही चिंतित हैं। नाटो के महासचिव ने भारत, चीन और ब्राजील को व्यापार जारी रखने पर प्रतिबंधों की चेतावनी दी है। ट्रंप भी धमकी दे रहे हैं।

भारत का रूस के साथ व्यापार, खासतौर से तेल आयात, अब अमेरिका और पश्चिमी देशों को बहुत अखरने लगा है। उन्‌होंने भारत पर तलवार लटका दी है। यह किसी ‘अग्निपरीक्षा’ से कम नहीं है। भारत पर अपनी ऑयल स्रट्रेंटेंजी को बदलने का भारी दबाव है। रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते भारत का रूसी तेल आयात पश्चिमी देशों के बयानबाजी का केंद्र बना हुआ है। नाटो के महासचिव मार्क रूटे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं ने भारत, चीन और ब्राजील को रूस के साथ व्यापार जारी रखने पर सेकेंडरी सैंव?शनस और भारी टैरिफ की चेतावनी दे दी है। इन धमकियों को रूस पर दबाव डालने की रणनीति का हिस्‌सा माना जा रहा है ताकि वह शांति वार्ता के लिए गंभीर हो। हालांकि, भारत ने अब तक रूस से अपने तेल आयात में कटौती नहीं की है। अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को उसने सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है।

वहीं, इकोनॉमिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेडरिसर्च इनिशिएटिव का मानना है कि भारत को रूस से तेल खरीदने के अपने फैसले पर अडिग रहना चाहिए। उसे अमेरिका के दबाव को खारिज कर देना चाहिए। जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के अनुसार, रियायती रूसी कच्चे तेल ने र?लोबल उथल-पुथल के बावजूद भारत को महंगाई कंट्रोल में रखने और मैक्रोइकोनॉमिक

स्थिरता बनाए रखने में भूमिका निभाई है। उनका तर्क है कि बाहरी दबाव में अपनी नीति बदलने से अमेरिकी धमकियां खत्म नहीं होंगी, बल्कि यह केवल और अधिक मांगों को दबत देगा। श्रीवास्तव ने यह भी जोड़ा कि वॉशिंगटन के साथ एक व्यापार सौदा भी संरक्षण की गारंटी नहीं देगा। कारण है कि ट्रंप बाद में टारगेट बदल



सकते हैं।

भारत पर लटक रही है तलवार

अमेरिका के साथ चल रहे व्यापार युद्ध और टैरिफ की अनिश्चितताओं के बीच भारत का रूस के साथ व्यापार फिर से पश्चिमी देशों की बातों में छया हुआ है। ये बातें रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर हो रही हैं। नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने बुधवार को कहा कि अगर भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश रूस के साथ व्यापार करना जारी रखते हैं तो उन्हें सेकेंडरी सैंक्शनस का बहुत बुरा असर झेलना पड़ सकता है। रूटे ने वॉशिंगटन में कहा कि रूस के साथ व्यापार करने

वाले देशों को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन करके कहना चाहिए कि उन्हें शांति वार्ता को लेकर गंभीर होना पड़ेगा। नहीं तो इसका ब्राजील, भारत और चीन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। कुछ हफ्ते पहले भारत में अमेरिका के एक बिल को लेकर चिंता जताई गई थी। इस बिल में रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 500 प्रतिशत



तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी धमकी दी थी कि अगर 50 दिनों के अंदर रूस-यूक्रेन के बीच शांति समझौता नहीं होता है तो रूसी सामान खरीदने वालों पर 100 प्रतिशत की दर से ‘कड़े’ सेकेंड्री टैरिफ लगाए जाएंगे। पुर्ना?िन पर दबाव बनाने की रणनी?ति इंडस्ट्री के जानकारों और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सब पुतिन पर दबाव बनाने की रणनीति है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि रूस से आयात करने वाले देशों पर दबाव बनाया जा सके। भारत ने अभी तक रूस से तेल का आयात

कम नहीं किया है। भारत का कहना है कि वह सबसे अच्छी कीमत पर तेल खरीदने को तैयार है, बशर्ते कि तेल पर कोई सैंक्शन न लगा हो। अभी रूसी तेल पर सीधे तौर पर कोई सैंक्शन नहीं है। लेकिन, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने 60 डॉलर प्रति बैरल की कीमत सीमा तय की है। इसके अनुसार, अगर रूसी तेल की कीमत इस स्तर से ऊपर जाती है तो पश्चिमी शिपर्स और इंश्योरेंस कंपनियां रूसी तेल के व्यापार में शामिल नहीं हो सकती हैं। भारत और चीन रूसी तेल के सबसे बड़े आयातक हैं।

भारत सरकार अमेरिकी सांसदों और ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत कर रही है ताकि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर अपनी चिंताएं बता सके। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 88 प्रतिशत आयात करता है। रूस लगभग तीन सालों से भारत के तेल आयात का मुख्य स्रोत रहा है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद पश्चिमी देशों ने रूसी तेल से किनारा कर लिया। इसके बाद रूस ने इच्छुक खरीदारों को अपने तेल पर छूट देनी शुरू कर दी। भारतीय रिफाइनर ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया। नतीजा ये हुआ कि रूस, जो पहले भारत को तेल की थोड़ी-बहुत सप्लाई करता था, अब भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है।

इसने पारंपरिक पश्चिम एशियाई स्र?लायर्स को पीछे छोड़ दिया है। समय के साथ छूट में बदलाव आया है। लेकिन, पश्चिमी देशों के दबाव और रूस के तेल व्यापार पर लगे सीमित सैंक्शनस के बावजूद भारत में रूसी तेल का प्रवाह मजबूत बना हुआ है। रूस के साथ बढ़ते तेल व्यापार ने रूस को भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों की लिस्ट में भी ला दिया है।

अभी इसे कई चुनौतियों से जूझना होगा

(अरविंद रावल)

आंकड़े बताते हैं कि भारत में अमीरों की संख्या बढ़ना भले ही बाजारवाद की दृष्टि से गर्व करने वाली बात हो, पर हकीकत यही है कि हमारे देश की एक बड़ी आबादी आज भी सरकार पर निर्भर है। ऐसे में, स्वाभाविक ही टेस्‌ला को कई चुनौतियों से जूझना होगा। एलन मस्क निस्संदेह दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में शुमार हैं और विश्व भर में उनकी कर्पनियों के उत्पाद बिकते हैं। मगर भारत के ऑटो बाजार में उनका उतरना शायद ही फायदेमंद हो सकेगा।असल में, भारतीय बाजार की रीढ़ मध्यमवर्गीय लोग हैं। ये वे लोग हैं, जिनकी सालाना आमदनी पांच लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक है। अधिकतर ये वाले लोग बेशक महंगी गाड़ियों का शौक रखते होंगे, लेकिन अधिकतर लोगों की पसंद सस्ती और टिकाऊ गाड़ियां होती हैं। इसके

विपरीत, एलन मस्क की टेस्‌ला कार अत्याधुनिक तकनीकी से लैस है, जिसके कारण इसकी शुरुआती कीमत 60 लाख रुपये रखी गई है। भारतीय सड़कों पर इतनी महंगी गाड़ियां गिनी-चुनी ही दिखती हैं। फिर, यहां तकनीक को कितने लोग आत्मसात कर पाए हैं? कई तो सिर्फ इसलिए किसी नई तकनीक से तोबा कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें उनकी अतिरिक्त ऊर्जा खर्च होगी। इसी कारण भारत में सस्ती गाड़ियां ज्यादा बिकती हैं। टाटा ने लखटकिया कार की संकल्पना भी इसी कारण से की थी। बाजार में आमतौर पर पांच से दस लाख तक की गाड़ियां ही ज्यादा दिखती हैं। ऐसे में भला 60-70 लाख रुपये की कितनी गाड़ियां टेस्‌ला कंपनी बेच सकेगी?एलन मस्क का भारतीय बाजार में अपनी बहुप्रतीक्षित टेस्‌ला कार बेचने का सपना देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पूरा हुआ है। वह लंबे समय से अपनी

इलेक्ट्रिक कार भारतीय बाजार में उतारना चाहते थे, लेकिन ऊंचे सीमा शुल्क के कारण उनकी कार की कीमतें भारत के लिहाज से काफी ज्यादा हो रही थीं, जिसके कारण उनका विचार लगातार टलता गया। चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में वह अमेरिकी प्रशासन का हिस्सा थे, इसलिए उनके लिए यहाँ शायद आसान हो गां। फिर भी, यदि उनको भारतीय ऑटो क्षेत्र में नेतृत्व करना है, तो मध्यवर्गीय लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर कारों बनानी होंगी। हां, जब यहाँ प्रतिव्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी या लोग इस लायक बन जाएंगे कि महंगी गाड़ियां आसानी से खरीद सकें, तब शायद टेस्‌ला की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग बढ़ जाए। तब तक तो एलन मस्क को भारतीय उपभोक्ताओं की मानसिकता को समझकर ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए।

चुनाव के आसपास बढ़ते भाषाई विवाद

नवनियुक्त राज्यसभा सांसद उज्जवल निकम ने जो बताया, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ने फोन पर सबसे पहले कहा कि मैं हिंदी में बात करूँ या मराठी में. निगम के अनुसार पीएम ने मराठी में बात करके मनोनयन की जानकारी दी. महाराष्ट्र में इस समय मराठी पर विवाद चरम पर है। दशकों पहले अलग हुए उद्भव और राज ठाकरे मराठी भाषा के नाम पर एक साथ आ गए हैं. महाराष्ट्र में नगरीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं. मुंबई महानगर पालिका के संभावित चुनाव मराठी विवाद के पीछे हैं. शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी मराठी भाषा में बात कर महाराष्ट्र के लोगों को संदेश दिया।

(सरयूसुत मिश्रा)

राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए गए चारों सदस्यों को पीएम ने स्वयं दूरभाष पर सूचना दी. पीएम की यह स्टायल है. राष्ट्रपति को जब उम्मीदवार बनाया गया था, तब भी पीएम ने ही उन्हें सबसे पहले बताया था...!!

नियुक्त राज्यसभा सांसद उज्जवल निकम ने जो बताया, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ने फोन पर सबसे पहले कहा कि मैं हिंदी में बात करूँ या मराठी में. निगम के अनुसार पीएम ने मराठी में बात करके मनोनयन की जानकारी दी. महाराष्ट्र में इस समय मराठी पर विवाद चरम पर है।

दशकों पहले अलग हुए उद्भव और राज ठाकरे मराठी भाषा के नाम पर एक साथ आ गए हैं. महाराष्ट्र में नगरीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं. मुंबई महानगर पालिका के संभावित चुनाव मराठी विवाद के पीछे हैं. शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी मराठी भाषा में बात कर महाराष्ट्र के लोगों को संदेश दिया।

चुनाव के आसपास अक्सर भाषाई राज्यों में भाषा के विवाद उत्पन्न किए जाते हैं. दक्षिण भारत के राज्यों में तो यह विवाद चलते ही रहते हैं. महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात बना था. लेकिन गुजरात में भाषा को लेकर उतना विवाद नहीं है, जितना कि महाराष्ट्र में मराठी को लेकर है. व्यवसाय में जहां लाभ है, वहां भाषा भुला दी जाती है।

मुंबई में ही हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है. वहां बनी हिंदी की फिल्में पूरी दुनिया में हिंदी भाषा पहुंचाती हैं. तमिल और दूसरी भाषा की फिल्मों को भी हिंदी में डबकर इसलिए दिखाया जाता है, क्योंकि देश में हिंदी का बाजार ज्यादा है. जैसे बाजार लाभ की भाषा में सोचता है, वैसे ही सियासत भी लाभ की ही भाषा समझती है।

सियासत बातें संविधान की करती है, लेकिन लाभ के लिए आचरण संविधान विरोधी करने लगती है. मराठी भाषा के मामले में जिस तरह से मुंबई में हिंदी भाषियों को मार-पीटा जा रहा है, वह न केवल अपराधिक कृत्य है, बल्कि संविधान विरोधी भी है।

भारत का संविधान सभी लोगों को देश के किसी भी राज्य में किसी भी स्थान पर रहने का, रोजगार करने का और जीवन यापन का अधिकार देता है. यही संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी अधिकार देता है. इसका मतलब है, कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में रह सकता है और अपनी भाषा में अभिव्यक्ति का उसे अधिकार है. जो हिंदी भाषी मुंबई में रहते हैं, उन पर



जबरदस्ती मराठी नहीं थोपी जा सकती. इसके उलट हिंदी देश की राजभाषा है. देश के सभी हिस्से में राजभाषा की शिक्षा त्रिभाषा फॉर्मूले में देना संविधान सम्मत है।

मराठी विवाद उद्भव ठाकरे और राज ठाकरे द्वारा मुंबई नगर पालिका चुनाव में राजनीतिक लाभ के लिए खड़ा किया जा रहा है. कोई भी ध्ववीकरण प्रसन्न होत प्रतुशत होता नहीं है. अगर मराठी ध्ववीकरण भाषा के नाम पर कुछ सीमा तक हो भी जाता है, तो भी मुंबई में हिंदी भाषियों की संख्या पर्याप्त है. दोनों भाइयों को जितना मराठी भाषा के नाम पर एकजुटता लाभ पहुंचा सकती है, उतना ही हिंदी भाषियों में उनका जनाधार कमजोर होगा. इनका गठबंधन

वैसे ही टूट गया है. मतलब कांग्रेस और एनसीपी मुंबई महानगर पालिका का अलग से चुनाव लड़ेंगे. यह सारे राजनीतिक गणित अभी धीरे-धीरे सामने आएंगे, लेकिन यह तो लगभग तय है कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन नहीं होगा।

संविधान निर्माता भाषाई विवाद के दूरगामी दुष्परिणाम को जानते थे. शायद इसीलिए देश में ऐसी व्यवस्था की गई कि अगर भाषा के नाम पर राज्यों की राजनीति बहकने लगे तब भी राज्य की सरकार राष्ट्रीय उद्देश्य और लक्ष्य के अनुरूप काम करती रहेगी. सरदार वल्लभभाई पटेल ने अखिल भारतीय सेवाओं का जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है, वह इतना मजबूत और प्रैक्टिकल है, कि कोई भी भाषा विवाद राज्य के प्रशासन को प्रभावित नहीं कर सकता है।

अगर भविष्य में ऐसी भी स्थिति बन जाए, कि भाषा के लिए सबसे अधिक आक्रामक राजनीति करने वाला नेता भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे जाए, तब भी राज्य प्रशासन को एकतरफा नहीं बनाया जा सकता. इसका कारण यह है, कि हर राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं आईएसएस और आईपीएस के फैडर में दो-तिहाई संख्या दूसरे राज्यों के अफसरों की रखी जाती है। किसी भी राज्य में जितने आईएसएस अफसर हैं. उनमें तीन में एक ही अफसर उस राज्य का होगा. बाकी दो अफसर दूसरे राज्यों के होंगे. इसका मतलब है कि जो दूसरे राज्यों के दो अफसर हैं वह या तो हिंदी, अंग्रेजी भाषा के होंगे या किसी भाषाई राज्य से संबंधित होंगे. अगर राज्य का पॉलिटिकल नेतृत्व क्षेत्रीय भाषा को आक्रामकता के साथ राजनीतिक उपयोग की कोशिश करेगा तो भी राज्य का दो तिहाई प्रशासन ऐसे अफसरों में कंट्रोल में रहेगा,

देते हुए कहा था कि कुछ देश अपनी नीतियों में सीमापार आतंकवाद को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और आतंकियों को पनाह दे रहे हैं। इसके बाद जब सम्मेलन का संयुक्त घोषणा-पत्र तैयार किया गया, तो उसमें पहलगाम आतंकी हमले का कोई जिक्र नहीं था और भारत ने इसका कड़ा विरोध किया था।इससे पाकिस्तान और चीन के मंसूबों का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। अगर ये देश वास्तव में आतंकवाद को खत्म करने की इच्छा रखते हैं, तो संयुक्त घोषणा-पत्र में पहलगाम हमले की निंदा करने से गुरेज क्यों किया गया? दौराय नहीं कि ऐसे दोहरे मापदंड को खत्म करना बेहद जरूरी है और एससीओ जैसे मंच को ऐसी ताकतों की खुलेआम आलोचना करनी चाहिए। अब जरूरी है कि आतंकवाद के वित्त पोषकों और प्रायोजकों को न्याय के कठपंरे में लाने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जाएं।

बादल जब उमड़ते हैं, वे जीवन की नई संभावनाएं लेकर आते हैं

(अनन्या मिश्रा)

बादल हमें यह भी सिखाते हैं कि हर घटना का एक उचित समय होता है। इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। यह वह धैर्य है जो अध्यात्म की नींव है। ‘कालः कर्षति भूतानि’, समय ही सबका निर्माता है।

क्या आपने कभी पहली वर्षा की उस गंध को महसूस किया है, जो तपती हुई धरती से उठती है? जैसे वर्षों पुराना कोई वादा पूरा हो गया हो? जैसे आकाश ने धरती को फिर से स्मरण किया हो? बादल जब उमड़ते हैं, तो वे जीवन की नयी संभावनाएं लेकर आते हैं। वर्षा केवल खेतों की नहीं, अंतरात्मा की भी सिंचाई करती है। वह बताती है कि उधराव के बाद गति और सूखे के बाद हरियाली भी संभव



है। जैसे बादल धीरे-धीरे आकार लेते हैं, वैसे ही साधना से भीतर की अनुभूति पूर्णता की ओर बढ़ती है। यहीं तो वेदों का संदेश है, कि ऋतुओं के परिवर्तन में ही ब्रह्म की गति है, और जब पहली बूंद गिरती है, तो वह चेतना की पुकार होती है।

वेदों में वर्षा को ‘ऋत्याय गर्भः’ कहा गया है, वह जो ऋतु (नियम, गति, धर्म) को जन्म देती है। प्रकृति की यह स्थायी पुनरावृत्ति हमारे भीतर की चेतना को एक नया प्रारंभ देती है। वर्षा का हर आगमन हमें यह सिखाता है कि हर अंत के बाद एक नव आरंभ संभव है। जब भूमि महीनों तक तपकर कठोर हो जाती है, तो वह पहली बूँद को आत्मसात कर फूल जाती है। हम भी जीवन में कई बार ऐसे कठिन काल से गुजरते हैं, जहां भावनाएं सूख जाती हैं, संबंध बंजर हो जाते हैं, और विश्वास की भूमि दरकने लगती है। लेकिन यदि धैर्य रखा जाए, तो भीतर का आकाश भी बादलों से भर सकता है। यह वर्षा केवल बाहर नहीं, भीतर भी घटती है। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है, ‘रिलायंस’ (प्रत्यास्थता), जिसका अर्थ है- कठिन परिस्थितियों से पुनः उठ खड़ा होने की क्षमता। यह वही है जो वृक्षों के सूखने के बाद पुनः हरे-भरे पत्तों से पूर्ण कर देता है। हमारी आत्मा में

एकसमान छूती है, यह समदृष्टि हमें सिखाती है कि आत्मिक दृष्टि किसी में भेद नहीं करती।

बादल हमें यह भी सिखाते हैं कि हर घटना का एक उचित समय होता है। इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। यह वह धैर्य है जो अध्यात्म की नींव है। ‘कालः कर्षति भूतानि’, समय ही सबका निर्माता है। साधना में भी यही होता है, हम जब भीतर की आग को सहते हैं, तब कोई अदृश्य शक्ति धीरे-धीरे बादलों को हमारे अंतरिक्ष में एकत्र करती है, और जब भीतर के तप की घड़ी पूरी होती है, तब वर्षा गिरती है। कभी वह करुणा बनकर, कभी मौन बनकर, कभी आत्म-ज्ञान की बूँद बनकर सामने आती है।

वर्षा की बूँद का स्थिर स्वर हमें भीतर के मौन से परिचित कराता है, जहाँ शब्द नहीं, केवल अनुभव होता है। प्रकृति के इस चक्र में एक और रहस्य है, हर वर्षा के बाद इंद्रधनुष का उगना। वह सात रंग जो इस बात का प्रतीक है कि जीवन में हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुःख, एक रंग है, और सब मिलकर ही पूर्णता बनाते हैं। यदि एक भी रंग न हो, तो इंद्रधनुष अधूर्ण है।

इसी प्रकार, जीवन में जो वर्षा हमें दुखी करती है, वही हमें रंगों से भर देती है।

जो मूल रूप से उस भाषा से बिलॉन नहीं करते हैं. जब इस व्यवस्था को बनाया गया था, तब संविधान निर्माताओं ने सोच लिया था, कि भाषा विवाद कभी ना कभी राज्य प्रशासन को प्रभावित कर सकते हैं।

अगर देश में आज संघवाद मजबूती के साथ काम कर रहा है, तो उम्मा भी एक बड़ा कारण अखिल भारतीय सेवाओं का स्ट्रक्चर कहा जा सकता है।

हिंदी संविधान के अनुसार भारत की आधिकारिक भाषा है. अंग्रेजी को एक निश्चित समय के लिए स्वीकार किया गया था, लेकिन वह सरकारी भाषा का रूप ले चुकी है. मराठी भाषा जो विवाद खड़ा किया जा रहा है, उससे बड़े-बड़े भाषा विवाद पहले हो चुके हैं. कई बार तो ऐसा लगने लगा था, कि कहीं देश का विखंडन भाषा के नाम पर ना हो जाए।

आजादी के बाद शुरूआती दिनों में भाषा के नाम पर बहुत विवाद हुए. अब धीरे-धीरे हमारा लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है. हिंदी धीरे-धीरे देश के कोने-कोने में फैल रही है. इसका एक बड़ा कारण हिंदी सिनेमा और टेलीविजन के साथ ही विभिन्न राज्यों की संस्कृतियों का आदान-प्रदान और संवाद माना जा सकता है।

जिन राज्यों में पहले हिंदी भाषी अगर जाएं तो उनकी भाषा समझने वाला कोई नहीं मिलता था, वह स्थिति अब किसी भी राज्य में नहीं बची है. हिंदी भाषी पर्यटक भाषाई राज्यों में बड़ी संख्या में जाते हैं. उत्तर भारतीयों के चार धामों में से एक महत्वपूर्ण धाम रामेश्वरम तमिलनाडु में है. वहां उतर भारत के लोग तीर्थ यात्र के लिए अनिवार्य रूप से जाते हैं. पहले वहां हिंदी भाषा समझने वाले नहीं मिलते थे, लेकिन अब केवल हिंदी भाषा जानने वाला संवाद शून्य नहीं रह सकता।

भाषा के नाम पर एक नई जंग विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते भारत के लिए बाधक बन सकता है. भाषाई अंधभक्ति राज्य के हितों का संरक्षण नहीं कर सकती है. जिस तरह से हिंदी भाषी लोगों का आवागमन भाषाई राज्यों में हो रहा है, वह धीरे-धीरे भाषा के बैरियर को महत्वहीन कर देगा.

स्वीकृति में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सल्लता को लेकर तब अनेक अड्डाचारों ने समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। 25 मार्च 2022 को भूपेश सरकार ने राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के रहते राजस्थान को कोल माईंस का आबंटन किया था।

भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष गुप्ता ने कांग्रेस के समाल किया कि क्या वह मनमोहन सिंह सरकार के समय हुए निर्णयों के लिए आज माफ़े मारिगे, क्या भूपेश बघेल यह घोषणा करे कि अब कांग्रेस क्या भी बिजली का उपयोग नहीं करेगी, क्योंकि स्वयं यह कह चुके हैं कि विरोध करने वाले अपने घर को बिजली बंद कर दें, क्या कांग्रेस हर अफसरों के पक्ष में ऐसे ही खड़ी होगी, जैसे आज पूर्व उपमुख्यमंत्री के बेटे के लिए हुंई है? गुप्ता ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही तब राजस्थान के तत्कालीन मंत्री बी डी कल्ल ने भूपेश बघेल को पत्र लिखा और राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सप्ताह के भीतर कई पत्र लिखे कोल ब्लॉक आबंटन के लिए। जिसे छत्तीसगढ़ और देश की जनता ने देखा है।

एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत किया।
वृक्षारोपण- वनमंत्री केदार कश्यप ने नवा रतेंगा,

